तारीखः 26दिसम्बर 2013

राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली का फेसबुक पोस्ट

केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार द्वारा कथित जासूसी करने के आरोपों की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित करने की घोषणा की है। उसकी यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। हाल के चुनावों में हुई पिटाई के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने सबक नहीं सीखा है। वह राजनैतिक स्तर पर नरेन्द्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रही है इसलिए वह जांच एजेंसियों और अब जांच आयोग का सहारा ले रही है।

इस मामले की जांच कराने के लिए गुजरात सरकार पहले ही जांच आयोग गठित कर चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा इस मुद्दे के बहाने एक से अधिक राज्यों के लिए समानान्तर आयोग गठित करने का कोई आधार नहीं है। उसकी यह कार्रवाई कानूनी तौर पर अनुचित है और इसे चुनौती दी जा सकती है। मुझे यकीन है कि इसे कानूनी तौर पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इस आयोग का गठन संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है। यह राज्यों का अपमान है।

मुझे उम्मीद है कि अन्य मुख्यमंत्री भी इस कार्रवाई का विरोध करेंगे।